



मार गई महंगाई



- ❖ Sushma Swaraj
- ❖ Arun Jaitley
- ❖ M. Venkaiah Naidu



BHARATIYA JANATA PARTY

The rule of Congress led UPA-II government is marked by unprecedented food inflation, high price rise, fiscal mismanagement, bad economics and complete chaos causing lots of hardships for *aam aadmi*. In its tenure so far UPA-II is now better known as *Mehangai Badhao Sarkar* catering to the whims and fancies of the hoarders and black marketeers. It is highly unfortunate to note that even in the face of repeated protests and criticisms the UPA-II government callously remains indifferent to the rising prices making the poor reel under heavy economic pressure. The recent hike in petroleum prices is an example of government's criminal apathy to the hardship people are facing in their daily life.

UPA-II is failing to control rising prices mainly because it lacks a vision that inspires its leaders to ameliorate the condition of the masses. It now banks on somehow befooling people at the time of elections through tokenism and hollow promises while acting contrary to people's expectations while coming to the power. The only mantra that guides it is the mantra of power. Somehow coming to the power and then using to serve vested interests of different cartels, profiteers, hoarders and black marketers is the sole goal of the Congress party. That's why its promise to rein in prices within 100 days of coming to power has come to a cropper. It could not uphold its promises to the masses because promises made to its patrons constituted of various cartels, profiteers, hoarders and black marketers outweighed its commitments to the people.

In the parliament Leader of the Opposition in Lok Sabha Smt. Sushma Swaraj took the government to task for failing to control prices even after repeated assurances. Leader of Opposition in Rajya Sabha Shri Arun Jaitley expressed his concern over dwindling credibility of the UPA government in the eyes of the people. Former BJP President Shri M Venkaiah Naidu said in the Rajya Sabha that the government was intentionally allowing the food grains to rot. We are publishing these speeches in the booklet to make everyone aware of the real issues behind the failure of the UPA-II in controlling the prices. We hope that this booklet will equip our readers to question the economic policies of the Congress led UPA government and arm them in the fight against unprecedented price rise.

**Publisher,
Bharatiya Janata Party
11, Ashoka Road, New Delhi**

August 2010

मार दिया इस महंगाई ने

I kkek Lojkt

आम आदमी आज जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, वर्तमान परिस्थिति को वह जिस शब्द से जानता और पुकारता है, वह एकमात्र शब्द है महंगाई। वह अपने दर्द को जिस वाक्य में अभिव्यक्त करता है, वह वाक्य है — मार दिया इस महंगाई ने। जब इस देश की गृहिणी बाजार में आटा, चावल, दाल, चीनी लेने जाती है या गैस वाले को पैसे पकड़ाती है, तो उसके मुंह से यही निकलता है — मार दिया इस महंगाई ने।



अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूँ: — चूंकि यह सभा अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव और आम आदमी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पर विचार करे।

अध्यक्ष जी, चर्चा पर सर्वसम्मति बनाने के लिए भले ही मुद्रास्फीति, इनफ्लेशन जैसे शब्दों पर सहमति बन गई हो, स्वीकार कर लिए गए हों, लेकिन मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि आम आदमी आज जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, वर्तमान परिस्थिति को वह जिस शब्द से जानता और पुकारता है, वह एकमात्र शब्द है महंगाई। वह अपने दर्द को जिस वाक्य में अभिव्यक्त करता है, वह वाक्य है — मार दिया इस महंगाई ने। जब इस देश की गृहिणी बाजार में आटा, चावल, दाल, चीनी लेने जाती है या गैस वाले को पैसे पकड़ाती है, तो उसके मुंह से यही निकलता है — मार दिया इस महंगाई ने। जब इस देश का गरीब अपनी लालटेन जलाने के लिए केरोसीन खरीदने जाता है, तो उसके मुंह से यही निकलता है — मार दिया इस महंगाई ने। जब 18-19 वर्ष का किशोर अपनी मां से स्कूटर के लिए पेट्रोल के पैसे मांगता है, तो मां और बेटा, दोनों के मुंह से एक साथ निकलता है — मार दिया इस महंगाई ने। जब घर में काम करने वाली

महिलाएं अपनी पगार बढ़ाने का तर्क देती हैं तो यही कहती हैं, क्या करें बीबी जी, मार दिया इस महंगाई ने। इसलिए मैं आज इस सदन में उस आम आदमी की तरफ से, उस गरीब गृहिणी की तरफ से, उस सतायी हुई महिला की तरफ से और उस परेशान नौजवान की तरफ से महंगाई पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूँ।

पिछले सत्र में जब बजट सत्र चल रहा था तब इसी सदन में महंगाई पर चर्चा हुई थी और समूचे सदन ने दलगत सीमाओं को लांघते हुए उस आम आदमी के दर्द को इस सदन में रखने का काम किया था। हमें लगता था कि सरकार इस महंगाई को रोकने का कोई कारगर उपाय करेगी। लेकिन हम हतप्रभ रह गए जब मात्र 24 घंटे के भीतर, 25 फरवरी को यह चर्चा हुई थी और 26 फरवरी को अपना बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री जी ने डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि की घोषणा कर डाली। हम सबको एक झटका सा लगा। हम सब शान्ति से बैठकर बजट भाषण सुन रहे थे। कोई पूर्व योजना नहीं थी, मगर सब अपनी सीट से उठ खड़े हुए। सब बहिर्गमन कर गए और केवल उस दिन के बहिर्गमन से नहीं, हमने इस सरकार पर तरह-तरह से दबाव बनाने की कोशिश की। आप जानती हैं कि कटौती प्रस्ताव जो पहले औपचारिकता मात्र आते थे, हम उसे तार्किक परिणति तक ले गए। हमने उस पर मतदान तक करवाया। यह अलग बात है कि लोकतंत्र संख्या के बल पर चलता है और सत्ता पक्ष के पास संख्या ज्यादा है, इसीलिए ये शासन में हैं। अतिरिक्त संख्या जुटाने के लिए सरकार हर हथकंडे का प्रयोग भी करती है। उस बार भी किया। मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहती। सारे देश ने देखा और समझा। लेकिन मैं एक बात कह सकती हूँ कि जो मत इन्हें पड़े थे, अगर उस मत में से बीएसपी सांसदों को घटा दिया जाए, तो सरकार अल्पमत में रह जाती। इस सदन का जादुई आंकड़ा 272 है। यह 543 का सदन है। इन्हें 289 मत पड़े थे। बीएसपी की संख्या 21 है। अगर उनकी संख्या घटा दें, तो 268 बच जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि तकनीकी तौर पर सरकार जीती थी, मगर प्रभावी तौर पर सरकार हारी थी। हमें यह लगा था कि जीतने के बाद भी इस सदन में आइना दिख गया, इसलिए यह सरकार आत्ममंथन करेगी, जनविरोधी नीतियों को रोकेंगी।

लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख है कि इस सरकार की हेकड़ी में रत्ती भर कमी नहीं आयी है। मात्र चार महीने बाद, पूरे चार महीने बनते हैं, 26

फरवरी को इन्होंने अपने बजट में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाये थे और 26 जून को, पूरे चार महीने बाद, इन्होंने दोबारा डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि की घोषणा की और इस बार इन्होंने केरोसिन और रसोई गैस को भी नहीं बख्शा। खाने की चीजें पहले से महंगी थीं। इन्होंने खाना पकाने का ईंधन भी महंगा कर दिया। अध्यक्ष जी, इसी को कहते हैं – कंगाली में आटा गीला और यह हिन्दुस्तान के गरीब के साथ हुआ। मैं कहना चाहती हूँ कि हमने ऐसी संवेदनहीन सरकार नहीं देखी। यह सरकार संवेदनहीन भी है और यह सरकार विश्वासघाती भी है।...(व्यवधान) कृतज्ञता का तकाजा था, आप दूसरी बार चुनकर आये थे, आम आदमी के नाम पर चुनकर आये थे।

अध्यक्ष जी, कृतज्ञता का तकाजा था कि यह उस आम आदमी को दोबारा चुनकर आने के बाद कोई राहत देते, लेकिन हुआ इसके विपरीत। चुनाव से पहले 60 रुपये किलो बिकने वाली दाल चुनाव के बाद 90 रुपये तक चढ़ गयी। चुनाव से पहले 25 रुपये बिकने वाली चीनी चुनाव के बाद 35 रुपये बिक रही है और अभी टीवी पर आ रहा है कि चीनी और कड़वी होगी। पता नहीं दाम कहां तक जायेंगे? चुनाव से पहले 17 रुपये किलो बिकने वाला आटा चुनाव के बाद 20 रुपये बिका। चुनाव से पहले 20 रुपये बिकने वाला चावल चुनाव के बाद 25 रुपये बिका और चुनाव से पहले 40 रुपये बिकने वाला पेट्रोल चुनाव के बाद 51 रुपये बिक रहा है। पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ गये, इसलिए हम क्या करें?

मैं पेट्रोलियम मंत्री जी से केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ या वित्त मंत्री जी बता दें कि जून 2008 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम क्या थे? जून 2008 में 134 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम था लेकिन तब आपने दाम नहीं बढ़ाये। आपने उस समय दाम क्यों नहीं बढ़ाये? आज 74 डॉलर प्रति बैरल है। प्रणब दा, क्या मेरे आंकड़े गलत हैं? वर्ष 2008 में 134 डॉलर प्रति बैरल थे और आज 74 डॉलर प्रति बैरल हैं। अब क्यों दाम बढ़ाये? अंतर केवल एक है— 2008 का साल चुनाव से पहले का साल था और 2010 का साल चुनाव के बाद का साल है और इसी को विश्वासघात कहते हैं कि आप चुनाव से पहले दाम नहीं बढ़ाते। लोगों को भरमाते हैं, गुमराह करते हैं, उनके नाम की दुहाई देते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं, तो आप उस आम आदमी को भूल जाते हैं और तब आप दाम बढ़ाते हैं।

अध्यक्ष जी, पेट्रोल और डीजल के दाम कैसे निर्धारित किये जाते हैं,

उसकी प्रक्रिया मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ। दाम का निर्धारण करने में चार तत्व आवश्यक होते हैं। पहला तत्व है – अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दाम। दूसरा तत्व है – जो कच्चा तेल आयात होता है, उस पर लगाने वाली कस्टम ड्यूटी। तीसरा तत्व है – जो यहां आकर कच्चा तेल परिशोधित होता है, रिफाइन किया जाता है, उस पर लगाने वाली एक्साइज ड्यूटी और चौथा तत्व है – राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला बियेरी कर। इन चारों चीजों को मिलाकर पेट्रोल का दाम तय होता है, जो उपभोक्ता देता है। मैं एक बार आपके सामने पड़ोसी देशों से तुलना करके बताना चाहती हूँ कि हम लोगों के यहां का कर पड़ोसी देशों से और विकसित देशों में सबसे विकसित देश से, अन्य विकसित देशों में ज्यादा है, लेकिन अमेरिका दुनिया का सबसे विकसित देश है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। उसकी तुलना में सबसे ज्यादा हमारे यहां का कर है। ये मेरे पास आंकड़े हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल पर 42 परसेंट, नेपाल में 31 परसेंट, बंगलादेश में 24 परसेंट, श्रीलंका में 37 परसेंट, अमेरिका में मात्र 14 परसेंट और भारत में 48 परसेंट कर है।

डीजल पर पाकिस्तान में 20 प्रतिशत, नेपाल में 22 प्रतिशत, बांग्लादेश में 24 प्रतिशत, श्रीलंका में 5 प्रतिशत, यूएसए में 16 प्रतिशत और भारत में 34 प्रतिशत टैक्स लगता है। सबसे ज्यादा कर हमारे यहां लगाया जाता है। आप राज्यों की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर हम राज्यों की तुलना करें, तो पेट्रोल पर सबसे ज्यादा कर है आन्ध्र प्रदेश में 33 प्रतिशत और डीजल पर सबसे ज्यादा कर है महाराष्ट्र में 26 प्रतिशत और दोनों ही राज्य कांग्रेसशासित राज्य हैं। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के दामों का सवाल है, हम उन पर नियन्त्रण नहीं कर सकते हैं। हम अपनी तेल की खपत का 80 प्रतिशत आयात करते हैं। हमारे देश में कुल खपत का केवल 20 प्रतिशत ही उत्पादित होता है। इसलिए बहुत बड़ी मात्रा के लिए हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार पर आश्रित हैं और वहां दाम निर्धारण हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम अपने कर का निर्धारण तो स्वयं करते हैं, हमें एक्साइज ड्यूटी कितनी लेनी है, हमें कस्टम ड्यूटी कितनी लेनी है, हमारे राज्यों ने सेल टैक्स कितना लेना है, यह तो हम तय करते हैं। अनेक बार यह अनुशंसा की गयी है कि हम इसको परसेन्टेज में न लगाकर, फ्लैट रेट से लगाएं। अगर हम फ्लैट रेट लगाएं तो उपभोक्ता दोहरी मार से बच जाएगा और केवल अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ा हुआ दाम उपभोक्ता पर बोझ डालेगा। लोग कहेंगे कि मैं क्या

कह रही हूँ, इसलिए मैं उनको साधारण भाषा में बताना चाहती हूँ, साधारण गणित में बताना चाहती हूँ। अगर कोई चीज 200 रुपये में आती है और उस पर 5 प्रतिशत टैक्स लगता है, तो वह चीज उपभोक्ता को 210 रुपये में मिलेगी। अगर 200 रुपये की उस चीज का दाम बढ़कर 220 रुपये हो गया, तो उपभोक्ता को 231 रुपये देने होंगे क्योंकि 220 रुपये वस्तु का दाम और उस पर 5 प्रतिशत की दर से 11 रुपये टैक्स लगेगा। अगर टैक्स हम 5 प्रतिशत की बजाय प्लैट रेट से 5 रुपये कर दें, तो उपभोक्ता को 200 रुपये की चीज पहले मिलेगी 205 रुपये में और दाम बढ़कर 220 रुपये होने पर भी उसे वही चीज मिलेगी 225 रुपये में क्योंकि कर 5 रुपये ही रहेगा। इस बात को इन्होंने एक्साइज ड्यूटी के रूप में मान ली है, वहां प्लैट रेट कर दिया, लेकिन कस्टम ड्यूटी के रूप में इसको नहीं मानते हैं। इन्होंने 5 प्रतिशत ड्यूटी यूपूड पेट्रोलियम, कच्चे तेल पर लगा रखी है, 7.5 प्रतिशत डीजल पर और 7.5 प्रतिशत पेट्रोल पर लगा रखी है। उस दिन प्रणव दा पूछ रहे थे कि क्या हम प्रस्ताव में कहें कि इमिडिएट स्टेप्स ले सरकार। तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे, तो क्या इमिडिएट स्टेप्स लिए जाएं, तो इसके बारे में मैं एक यही सुझाव आपको देती हूँ। आप यह इमिडिएट स्टेप ले सकते हैं कि अपने रिजीम के रेवेन्यू न्यूट्रल रिजीम तो बना सकते हैं। हम कम से कम कर का अतिरिक्त भार उपभोक्ता पर न डालें। लेकिन अभी यह हालत है कि जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ते हैं, तो वित्त मंत्री की बांछें खिल जाती हैं कि खजाना भरने का समय आ गया। जैसे ही दाम बढ़ेगा, उसके ऊपर अतिरिक्त कर भी बढ़ेगा और इस तरह मेरा खजाना भी बढ़ेगा। आप ऐसा नहीं करते हैं और आप राज्यों को कहते हैं कि बिक्री कर कम कर दो। राज्य कहते हैं कि आपके पास कर लगाने के इतने अधिकार हैं, आप अपने कर कम नहीं करते हैं और हमें कहते हैं कि कर कम कर दो। इसे कहते हैं – औरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप स्वयं रेवेन्यू न्यूट्रल रिजीम लाएं, तो आप में नैतिक बल आएगा राज्यों को कहने के लिए कि आप भी इसे रेवेन्यू न्यूट्रल रखिए। अगर राज्यों को कहते हैं, तो सबसे पहले आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से कहिए, वहां से शुरू कीजिए। आप उनको क्यों नहीं कहते हैं? वे आपके द्वारा शासित राज्य हैं। आप अन्य राज्यों को ही कहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपने यह पूछा कि इमिडिएट स्टेप्स क्या हों। ...दिल्ली से बात नहीं बनती है, मैं इनकी बात कर रही हूँ। अगर कस्टम ड्यूटी पऊलैट रेट पर हो जाती है, तो कर

का अतिरिक्त भार उपभोक्त पर नहीं पड़ेगा। तत्काल लिए जाने वाले कदमों के बारे में मेरा पहला सुझाव यह है कि आप रेवेन्यू न्यूट्रल रिजीम लाइए और उससे आप उपभोक्ता को राहत दे सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी बात रसोई गैस और केरोसिन ऑयल के बारे में करना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, केरोसिन ऑयल कौन बरतता है, या तो वह जो निम्न मध्यम वर्ग की महिला है, जो स्टोव पर खाना पकाती है, उसका तो बजट आपने वैसे ही गड़बड़ा दिया है, आटा-दाल-चीनी के दाम पहले से ही बढ़े थे, अब केरोसिन ऑयल का दाम भी बढ़ा दिया, वह तो लुढ़क गई। दूसरा कौन केरोसिन ऑयल इस्तेमाल करता है, जिस गरीब के घर में बिजली नहीं पहुंची, जो लालटेन जलाता है, जिसके पास लालटेन के भी पैसे नहीं, जो डिबरी जलाता है, वह केरोसिन ऑयल यूज करता है। रसोई गैस हर मध्यम वर्ग की महिला इस्तेमाल करती है। इस रसोई गैस ने उसे चूल्हे और अंगीठी से निजात दिलाई है। उसकी आंखें चूल्हे से फुंका करती थीं और अंगीठी के कोयले का धुंआ जाता था इसलिए वह रसोई गैस इस्तेमाल करने लगी। अब आप वापस उसे चूल्हे और अंगीठी की तरफ भेज रहे हैं। देहातों में लोग कहने लगे हैं, महिलाएं बात करने लगी हैं कि इतनी महंगी गैस नहीं पुगती, केवल चाय-चाय इस पर बना लिया करेंगे, घर के उपले, घर की लकड़ी है, वापस चूल्हा फूंकना पड़ेगा, वापस दो वक्त की रोटी चूल्हे पर बनाएं, क्योंकि इतनी महंगी गैस हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मगर ये कहते हैं कि हमने तो मात्र तीन रुपए लीटर केरोसिन ऑयल पर बढ़ाए हैं और सिर्फ 35 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाए हैं। मात्र तीन रुपया, मात्र 35 रुपया, यह बस नहीं है अध्यक्ष जी, यह केवल इब्टेदा है, केवल शुरुआत है, क्योंकि इन्होंने ऐसी-ऐसी कमेटीज बिठा दी हैं, जो केवल गरीबमार सिफारिशें कर रही हैं। एक कमेटी, केलकर कमेटी, हमारे समय बैठी थी। उसकी सिफारिश मानकर हम तो आज तक नहीं उबर पा रहे हैं प्रणव दा, आप कहेंगे कि आपने यह किया था, लेकिन मैं खुद इसे कह रही हूँ। उसकी सिफारिशें मानकर हम तो आज तक नहीं उबर पा रहे, आपने तो तीन-तीन कमेटीज बिठा दी हैं। एक रंगराजन कमेटी है, दूसरी चतुर्वेदी कमेटी है और तीसरी किरीट पारीख कमेटी। यह सारा किया-धरा उस किरीट पारीख कमेटी का है, जो केरोसिन ऑयल में, डीजल में और एलपीजी में वृद्धि देखने को मिल रही है। यहीं बस नहीं है, मैं किरीट पारीख कमेटी की सिफारिशें आपको पढ़कर सुनाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। शरद भाई, जरा सुन लीजिए कि किरीट पारीख ने क्या कहा है। एक सिफारिश है,

"The price of PDS kerosene should be increased by at least Rs.6 per litre. Thereafter, the price of PDS kerosene should be raised every year in step with the growth in per capita agricultural GDP at nominal prices."

यानि छः रुपए प्रति लीटर तो अभी बढ़ाओ और हर साल मिट्टी के तेल का दाम बढ़ाते जाओ। यह किराट पारीख कमेटी की सिफारिश है। उनकी दूसरी सिफारिश सुनिए,

"The prices of domestic LPG should be increased by at least Rs.100 per cylinder. Thereafter, the price of domestic LPG should be periodically revised based on rise in per capita income." अभी 100 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाओ, फिर बाकी रिवाइज करते जाओ, बढ़ाते जाओ। उनकी तीसरी सिफारिश है,

"The subsidy on domestic LPG should be discontinued for all others except the BPL households once an effective targeting system is in place."

वह कहते हैं कि डोमेस्टिक एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी बीपीएल के अलावा बाकी लोगों के लिए खत्म करो। ये सिफारिशें हैं किराट पारीख कमेटी की और ये सिफारिशें केवल सिफारिशों तक ही नहीं हैं, मैंने पहले ही कहा है कि ये गरीबमार सिफारिशें हैं। ये सिफारिशें सरकार मानने की मंशा रखती है।

इसी सत्र में एक सवाल पूछा गया था। सवाल नम्बर 72 है, हमारे जबलपुर के सांसद राकेश सिंह जी और दूसरे सांसद पी. करुणाकरण जी हैं। उन्होंने यह सवाल पूछा था। इसका जवाब पेट्रोलियम मंत्री जी ने दिया है। मैं उस जवाब को पढ़कर बताना चाहती हूँ कि मंत्री जी ने क्या कहा है:

"To reduce the under-recovery burden of the OMCs as also to protect the common man, the Government decided to increase the retail price of PDS kerosene by only Rs.3 per litre and of domestic LPG by only Rs.35 per cylinder. This is against the required increase of Rs.18.82 per litre in PDS kerosene and Rs. 261.90 per cylinder in domestic LPG."

यह उत्तर उन्होंने दिया है कि केरोसिन ऑयल में 18 रुपए 82 पैसे की वृद्धि होनी चाहिए। रसोई गैस 261 रुपए 90 पैसे प्रति सिलेंडर और बढ़नी चाहिए यानि करीब 550 रुपए का तो सिलेंडर होना चाहिए और केरोसिन प्रति लीटर करीब 30-32 रुपए होना चाहिए। उनकी ये सिफारिशें थीं।

उन्होंने कहा कि हमने आम आदमी को बचाने के लिए केवल लिए ही कीमतों में वृद्धि की है। इसके साथ उन्होंने अपेक्षित वृद्धि बता दी कि केरोसीन के लिए 18.82 पैसे चाहिए और सिलेंडर के लिए 261.90 पैसे चाहिए। सवाल यह था कि वृद्धि क्यों की गई है। इसका उत्तर दिया कि हमने इसलिए इसे बढ़ाया है कि हम आम आदमी के लिए सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए अधिक निधि आबंटित की जा सके। इस बात को पेट्रोलियम मंत्री ने केवल यहीं नहीं कहा, बल्कि मैं आज अखबार में पढ़ रही थी कि कांग्रेस संदेश नाम की पत्रिका निकलती है, जिसमें सोनिया जी का लेख है। उसमें उन्होंने हू-ब-हू यही बात कही है कि पेट्रोलियम के दाम बढ़ाने की अनिवार्यता हो गई थी, क्योंकि आम आदमी के लिए जो सामाजिक योजनाएं चला रहे हैं, उनमें हम अधिक धन देना चाहते हैं। सोनिया जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन महोदय मैं आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहती हूँ— "आज की रात बचेंगे, तो सहर देखेंगे।" अगर कोई आदमी महंगाई के इस काल से बचेगा, तो ही आपकी योजनाओं का लाभ लेगा। अगर इस महंगाई के काल में आदमी मर ही जाएगा, तो सामाजिक योजनाओं का क्या लाभ प्राप्त करेगा? यह कौन-सा तरीका है कि तुम्हारे लिए हमें योजनाएं चलानी हैं, उनके लिए धन जुटाना है इसलिए हम तुम्हारे ऊपर यह बोझ डाल रहे हैं। यही नहीं, रसोई गैस, केरोसीन, डीजल और पेट्रोल के दामों में तो सार्वजनिक रूप से वृद्धि की गई, इसीलिए सभी लोगों को पता है। लेकिन कुछ ऐसी गैसों के दाम भी बढ़े हैं, जिनके बारे में आम आदमी को पता नहीं है। सदन में आगरा के सांसद बैठे हैं। वे आगरा का प्रतिनिधि मण्डल लेकर प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए गए थे। आगरा में एपीएम गैस इस्तेमाल की जाती है। आगरा में इस गैस को सुप्रीम कोर्ट से इस्तेमाल करने की अनिवार्यता है, क्योंकि ताजमहल की सुरक्षा के लिए वहां औद्योगिक इकाइयों के लोग इस गैस के अलावा कोई दूसरा ईंधन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मैं सदन को बताना चाहूंगी कि एपीएम गैस के 60 प्रतिशत दाम बढ़ाए गए हैं। जब आगरा का प्रतिनिधि मण्डल प्रधानमंत्री जी से इस बाबत मिला, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसे देखूंगा, लेकिन अगले दिन ही एपीएम गैस के 60 प्रतिशत दाम बढ़ गए। दो लाख लोग वहां छोटी औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे हैं और उन्हें सवा लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन आवश्यकता होती है। जिन फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए इसे बढ़ाया गया है, वहां सौ लाख की आवश्यकता होती है। आप यह बताएं कि उन लोगों को जिनके साथ

प्रतियोगिता करनी है, उन औद्योगिक इकाइयों पर ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है, वे चाहे जो भी ईंधन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैसे उनके प्रतियोगी रहेंगे? अगर 60 प्रतिशत गैस के दाम बढ़ा कर कहेंगे कि आप अपनी औद्योगिक इकाई चलाएं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की अनिवार्यता है इसलिए आप कोई दूसरा ईंधन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो वे कैसे दूसरी औद्योगिक इकाइयों के प्रतियोगी रहेंगे? इसी कारण मैं पेट्रोलियम मंत्री से कहना चाहती हूं कि रसोई गैस, केरोसीन, डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़ाए हैं, उनसे आम आदमी अवगत है, लेकिन आगरा के लोगों की तरफ से आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आपने एपीएम गैस के जो दाम बढ़ाए हैं, एक विशेष परिस्थिति में आप आगरावासियों के लिए राहत देने का काम कीजिए और कीमत में जो वृद्धि आपने की है, उसे वापिस लेने का काम कीजिए।

महोदया, जब हम इस प्रकार की बातें पेट्रोलियम मंत्री से करते हैं, तो वे एक तर्क देते हैं कि हम क्या करें, हमारी तो कम्पनियां बहुत घाटे में चल रही हैं। हमारी तेल कंपनियों का घाटा हम कैसे पूरा करेंगे और वे मुझे अलग से नहीं कहते। इतना बड़ा विज्ञापन इस वृद्धि के बाद पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा दिया गया और उस विज्ञापन में लिखा कि इस वृद्धि के बाद भी इन कंपनियों को 53000 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ेगा। पूरे देश के सामने यह कहा गया कि 53,000 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ेगा। इससे बड़े असत्य और निराशा की बात नहीं हो सकती। मैं पेट्रोलियम मंत्री जी को उन्हीं के अपने उत्तर से आइना दिखाना चाहती हूं। उन्हीं के अपने उत्तर से मैं उनको कंफ्रन्ट करना चाहती हूं। पेट्रोलियम मंत्रालय की जो वर्ष 2009-2010 की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में जो सबसे बड़ी कंपनी इंडियन ऑयल कंपनी है, उसके लिए कहा है। यह आपकी रिपोर्ट है, जो आपने रखी है:-

"During 2008-09, IOC posted net profit of Rs.2950 crore on an unprecedented turnover of Rs. 2,85,337 crore"

जिस कंपनी का टर्न ओवर 2,85,337 करोड़ है, जिस कंपनी ने 2950 करोड़ रुपये वर्ष 2008-09 में कमाए, उसके लिए कहते हैं कि वह घाटे में चल रही है औरAnd that too after holding the price line for the four major products like petrol, diesel, PDS kerosene and LPG for domestic use. यानी पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और केरोसिन के दाम स्थिर रहते हुए यह मुनाफा उन्होंने कमाया। उसके बाद कहते हैं कि:-

"...IOC is also the first and the highest ranked Indian company in the Fortune Global 500 placed at 105th position by sales in 2009. The profit after tax for the year 2009-10 upto December, 2009 is Rs. 4663.78 crore whereas the turnover for the said period is Rs. 208289.46 crore."

यह तो आपकी वार्षिक रिपोर्ट है। लेकिन उसके आगे मैं बताती हूं। एक और सवाल है। इसी सत्र का सवाल प्र.सं. 89 है और यह पूछा गया कि आपकी तेल कंपनियों का प्रॉफिट और लॉस क्या है? पेट्रोलियम मंत्री द्वारा इस सदन में 29 जुलाई का दिया गया जवाब है। तीनों कंपनियों का प्रॉफिट बताती हूं और क्या लिखा है:-

"The profit after tax realized by the public sector oil marketing companies since 2006-07 is given below."

मैं वर्ष 2006-07 का भी नहीं, 2007-08 का भी नहीं, लेकिन जो आज का है क्योंकि कह सकते हैं कि तब था लेकिन अब हम घाटे में नहीं हैं। अध्यक्ष जी, मैं इसे पढ़कर सुना रही हूं। मैं आपका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। 2009-10 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने टैक्स देने के बाद नैट मुनाफा 10,221 करोड़ रुपया कमाया। भारत पेट्रोलियम ने 1538 करोड़ रुपया मुनाफा कमाया और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने 1301 करोड़ रुपया मुनाफा कमाया। यह मेरे द्वारा गढ़े गये आंकड़े नहीं हैं। इस सदन में पेट्रोलियम मंत्री द्वारा इसी सरकार ने 29 जुलाई को जो इस सदन में आंकड़े दिये हैं। ये वे आंकड़े हैं।... और इनका पेट्रोलियम मंत्रालय कहता है कि 53000 करोड़ रुपये का घाटा इस वृद्धि को देने के बाद घाटा होगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आखिर क्या हो रहा है? आप अपनी एनुअल रिपोर्ट में फॉर्चून ग्लोबल 500 की कंपनियों की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। इस सदन में आप कहते हैं कि आपकी तीनों कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं लेकिन आप यहां सदन में बोलते हुए कहते हैं कि हमारी कंपनियां घाटा उठा रही हैं, इसलिए हम क्या करें? सवाल यह नहीं है कि कंपनियां घाटा उठा रही हैं। सवाल यह है कि वित्त मंत्री अपना बजट घाटा पूरा करना चाहते हैं।

पूरे पेट्रोलियम सैक्टर में पिछली बार यूटी और डिवीडेंड के मुताबिक 90,000 करोड़ रुपये इन्हें दिया।

यह बात किसी और ने नहीं बल्कि इन्होंने तीन दिन पहले स्वयं सदन में कहा था जब मैं, आडवाणी जी और अरुण जी से मिलने गए थे। इन्होंने

हमें जीएसटी के बारे में बुलाया था और कहा था कि 1,18,000 करोड़ का नेट टैक्स पेट्रोलियम सैक्टर से आया है और 24,000 करोड़ स्टेट्स को दिया है और 94,000 करोड़ हमें मिला है। ...

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): The States have got Rs. 96,000 crore and I got Rs. 84,000 crore.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ (VIDISHA): I correct myself- आपको 84,000 करोड़ रुपया मिला। ... (व्यवधान) इन्होंने मान लिया कि इन्हें 84,000 करोड़ रुपए मिले।

अध्यक्ष महोदया, बजट एप्रूव करना हमारी मजबूरी है, हम चाहें या न चाहें सहमत हों या न हों। प्रणब दा 84,000 करोड़ स्वयं मान रहे हैं, इस वृद्धि के बाद 1,20,000 करोड़ रुपए मिलेगा और मैं कहना चाहती हूँ कि उसका बोझ आम आदमी पर पड़ेगा। मेरे इस वाक्य को सुनिए कि 84,000 करोड़ रुपए से 1,20,000 करोड़ करके इन्होंने अपना बजट घाटा तो सुधार लिया लेकिन आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया। मेरा यह आरोप है। यहां माननीय प्रधानमंत्री बैठे हैं, मैं पेट्रोलियम और वित्त मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि गरीबों की बददुआ मत लीजिए, वे तो पहले ही मर रहे हैं। मीडिया से पेट्रोलियम मंत्री से बात करते हैं तो कहते हैं – क्या हुआ, तीन रुपया प्रति लीटर केरोसीन बढ़ा, अगर कोई 10 लीटर लेगा तो 30 रुपया देगा इस तरह से एक ही रुपया तो एक दिन का बढ़ा, 35 रुपया प्रति सिलेंडर बढ़ा, क्या हुआ, एक रुपया कुछ पैसे ही तो बढ़े। यहां माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि आपका एक मंत्री कहता है – क्या हुआ अगर एक रुपया केरोसीन पर बढ़ा, क्या हुआ गैस पर बढ़ा।

महोदया, एनडीए की बात तो मैंने स्वयं स्वीकार कर ली है, नारायणसामी जी क्यों खड़े हो रहे हैं। एनडीए की बात तो मैंने पहले ही स्वीकार कर ली है, हम एक कमेटी के मारे हैं और आप तीन कमेटी के मारे हैं। मैंने तो कहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जब पेट्रोलियम मंत्री आकर कहेंगे – एक रुपया प्रति लीटर केरोसीन पर बढ़ा तो क्या फर्क पड़ा? एक रुपया गैस पर बढ़ा तो क्या फर्क पड़ा? इसी तरह से खाद्य मंत्री कह देंगे – एक रुपया प्रति किलो चावल पर बढ़ा, दो रुपए प्रति किलो दाल पर बढ़े तो क्या फर्क पड़ा? एक रुपया चीनी पर पड़ा तो क्या फर्क पड़ा? इस तरह से एक जमा एक करते जाएंगे लेकिन आप उस गरीब आदमी की तो सोचिए जिसे केवल बीस रुपए रोज के मिलते हैं। अगर एक जमा एक करते

जाएंगे तो वह कहां बचेगा? सरकारी आंकड़े हैं, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रखी गई, वह कहते हैं कि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोग रोज बीस रुपए पर जीते हैं। ...

अगर रोजाना खर्च के हिसाब से लगाना है तो अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट में प्रतिदिन आमदनी बताई गई है कि रोजाना बीस रुपए आमदनी से करोड़ों लोग जी रहे हैं। आप एक जमा एक करते जा रहे हैं और अल्टीमेटली यही रिजल्ट होगा – आमदनी अट्टनी और खर्चा रुपया। आज गरीब की यही हालत हो रही है। वह भूखा मर रहा है। यहां शरद जी, फूड एंड कन्ज्यूमर मिनिस्टर हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि यह अजीब विडंबना है कि एक तरफ गरीब भूखा मर रहा है और दूसरी तरफ लाखों टन अनाज गोदामों में सड़ रहा है।

राजनाथ जी यहां बैठे हैं। पिछली बार राजनाथ जी हरियाणा में पलवल के पास एफसीआई के गोदाम में गए थे और वहां से वह गेहूं लेकर आये थे। उन्होंने वह गेहूं आपको भी दिखाया था और आप देखकर हैरान हो गई थीं कि यह गेहूं है। क्या वह गेहूं लगता था, वह कचरे का ढेर लगता था। वह उन्होंने दिखाया, लेकिन बात वहीं बस नहीं हुई। मेरठ के सांसद श्री राजेन्द्र अग्रवाल यहां बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले वह हापुड़ होकर आये हैं। दैनिक जागरण ने उनके बारे में छापा है, एफसीआई प्रकरण में सीबीआई की जांच मांगी है। हापुड़ में लाखों टन गेहूं की बोरियां भीग रही हैं। हमारे एक पूर्व सांसद श्री किरिट सोमैया कल लखनऊ से 180 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर में एफसीआई के गोदाम में गए थे। शरद भाऊ, आप पुछवा लेना। 3,97,000 बोरी गेहूं बाहर भीगकर खराब हो गया। वह 7,18,000 बोरी का गोदाम है, जिसमें 3,97,000 बोरियां बाहर पड़ी हैं। वह अपने साथ पूरी तस्वीरें और सैम्पल्स भी लाये हैं। लेकिन सदन की मर्यादा के कारण मैं तस्वीरें और सैम्पल्स नहीं दिखा सकती। लेकिन यह सब मैं आपको भी पहुंचा दूंगी और शरद भाऊ आपको भी पहुंचा दूंगी। एक अकेले एफसीआई के गोदाम के बाहर 3,97,000 बोरियां सड़कर पड़ी हैं। गोदामों में अनाज सड़ रहा है। हमारी राज्य सरकारें इनसे खाद्यान्न मांग रही हैं कि भूखे और गरीब लोगों को खाद्यान्न दे दें तो वहां सरकार ना-नुकर करती है। मैं तीन मुख्य मंत्रियों के आंकड़े लाई हूँ। अभी एनडीसी की मीटिंग में हमारे उत्तराखंड के मुख्य मंत्री ने इनसे कहा कि 80,343 मीट्रिक टन गेहूं और चावल की हमारी मांग है। जिसमें 41,578 मीट्रिक टन गेहूं और 38,771 मीट्रिक टन चावल हमें

चाहिए और उन्होंने अपने यहां के राशन कार्डर्स का हिसाब बताया कि 22,09,567 राशन कार्डर्स हमारे यहां हैं और इनके लिए हमें 80,343 मीट्रिक टन अनाज चाहिए। लेकिन आप उन्हें 34,521 मीट्रिक टन दे रहे हैं। 45,828 मीट्रिक टन आप कम दे रहे हैं।

हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जून, 2008 से आपको पत्र लिख रहे हैं। उन्होंने पहले आपको पत्र लिखा, फिर प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा कि हमारे यहां साठ लाख बीपीएल कार्डधारी हैं। आप उन्हें 41 लाख दे रहे हैं, 21 लाख आप उन्हें नहीं दे रहे हैं। यह उनका हाल है।

हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री, जो इस देश में सबसे ज्यादा बढ़िया पीडीएस चला रहे हैं। वहां हर सात तारीख को 35 किलो गेहूं और चावल का आबंटन हो जाता है। उन्होंने आपसे अतिरिक्त मांगा, आपने उन्हें अतिरिक्त दिया, परंतु पूरा नहीं दिया, कम दिया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि उसमें भी आप पैसा कमाते हैं। सरकार ने गेहूं और चावल की एपीएल की दर तय की हुई है। एपीएल का सेंट्रल इश्यु प्राइस छः रुपये दस पैसे है, जिस दर पर आप देते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री को जो अतिरिक्त अनाज दिया गया, वह साढ़े आठ रुपये के हिसाब से दिया गया। एपीएल की गेहूं की दर आठ रुपये पैंतालीस पैसे है और उन्हें 11 रुपये 85 पैसे के हिसाब से दिया। अनाज सड़कर खत्म हो जाए, उसका एक नया पैसा न मिले, वह मंजूर है। लेकिन वह व्यक्ति जो भूखों और गरीबों को खाद्यान्न खिला रहा है, यहां तक एपीएल के लोग, कोई बहुत बड़े संभ्रांत लोग नहीं हैं, वे बाजार से नहीं खरीद सकते। आप उनसे छः रुपये दस पैसे की बजाय साढ़े आठ रुपये लेते हैं। साढ़े आठ रुपये की जगह 11 रुपये 85 पैसे लेते हैं और फिर भी पूरा आबंटन नहीं करते, कहते हैं कि अस्थायी आबंटन है। यही स्थिति अन्य कांग्रेस शासित राज्यों की भी होगी। मैं केवल अपने तीन राज्यों के मुख्य मंत्रियों के आंकड़े लेकर आई हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि इस विडम्बना को आप कैसे दूर करेंगे। राज्य खाद्यान्न मांग रहे हैं, लोग भूखों मर रहे हैं। सस्ते में राशन उपलब्ध नहीं हो रहा है और आपका अनाज सड़ रहा है। दोनों में कोई तालमेल नहीं है। आपकी संवेदना कहां चली गई? आप उन राज्यों को वह अनाज क्यों नहीं दे देते, ताकि वे अपने भूखे और गरीब लोगों को खिला दें। वह आपसे पैसे देकर मांग रहे हैं, मुपकृत नहीं मांग रहे हैं। लेकिन आप उनसे बढ़ा हुआ पैसा ले रहे हैं। मैंने आपसे तभी कहा था कि यह संवेदनहीन सरकार है, इसे झकझोरने की जरूरत है। यह सरकार कान भीचकर चल रही

है, आंख मीचकर चल रही है। इसीलिए हम तब एडजर्नमेंट मोशन लाये थे, नियम 184 के तहत चर्चा का प्रस्ताव लाये थे। लेकिन उन पर एक सहमति नहीं बनी। अब यह मोशन आया है। लेकिन इस मोशन के तहत भी मैं पूरे सदन से कहना चाहती हूँ कि महंगाई के मुद्दे पर हम सदन को बांट नहीं रहे हैं।

महंगाई पूरे देश का दर्द है। दिक्कत यह है कि हम विपक्ष में हैं, खुलकर बोल लेते हैं। प्रणब दाँ, आपके लोगों का भी यही मनोभाव है, आपके सहयोगी दलों का भी यही है और आपके समर्थक दलों का भी यही है। समर्थक दल दबी जबान में बोलते हैं जबकि आपकी पार्टी के लोग नहीं बोल पाते हैं लेकिन सभी लोगों की मनोभावना एक ही है कि महंगाई रुकनी चाहिये। अध्यक्ष महोदया, अगर मैं शुद्ध विपक्ष की राजनीति करूँ तो यह सरकार जितनी जल्दी अलोकप्रिय हो, मुझे अच्छा लगेगा जिसमें हमें फायदा होगा। लेकिन मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि फायदा और नुकसान व्यापार की भाषा है और हम लोग व्यापारी नहीं हैं। हम देश की जनता के हित के प्रहरी हैं जिन्होंने हमें यहां चुनकर भेजा है। आज हम पहरेदार की भूमिका निभाते हुये, यह प्रस्ताव मैं आपके सामने रख रही हूँ। मैं यह भी कहना चाहूँगी कि भले आप सत्ता पक्ष में हैं लेकिन पहरेदार आप भी हैं। आप जनहित के प्रहरी बनकर यहां बैठे हैं, भले ही आप शासन में हैं और हम विपक्ष में हैं। या कुछ लोग आपके समर्थक दल और कुछ सहयोगी दल हैं। इसलिये मैं इस प्रस्ताव को यहां प्रस्तुत करते समय समूचे सदन से करबद्ध अनुरोध करना चाहती हूँ कि आइये, इस प्रस्ताव को पारित करते हुये सरकार से आह्वान करें कि सरकार अपनी नींद से जागे और उस आम जनता को, जिसे सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उसे तुरंत और तत्काल प्रभाव कदम उठाकर राहत देने का काम करे।

धन्यवाद।



Credibility of Congress led UPA Govt. is at stake

Arun Jaitley



Participating in the debate on Inflationary pressure on the economy and its adverse impact on the common man the Leader of Opposition in the Rajya Sabha Shri Arun Jaitley on August 04 said, severely criticized the wrong Economic policies of Congress led UPA government and highlighted the plight of common man during Congress led rule. Full text of the speech:

Mr. Deputy Chairman, Sir, in the last 14 months of UPA-II, we have discussed the issue of price rise and inflation in almost every Session of Parliament and during each debate, this Government has held out assurances in this House and outside this House that it expects prices to moderate very soon.

Sir, I recently came across a tabulation which a national daily prepared. Way back on 8th November 2009, the Deputy Chairperson of the Planning Commission said that by the end of this financial year, food inflation will come down. It went up by the end of the year to almost 20 per cent. On 18th February 2010, the Finance Minister said that the country would see a moderate rate of inflation in the next two months. The general inflation has gone into double digit. The Agriculture Minister again in February said that food prices have already started falling down. I think, it is safe to presume that he does not visit the grocery shops or the vegetable shops. I have a list of the Prime Ministerial statements. On 6th February, it was said that the worst is over as far as inflation is concerned. In

May, we are told that now it will slow down and reach 5-6 per cent by December.

Sir, I must say, with all my personal admiration for the Prime Minister who is here, we seem to be losing faith as far as the assurances of this Government are concerned. There is a certain kind of paralysis, a drift, which has hurt this Government. Why we insisted on a voting motion and not a debating motion? Because, voting motions are also intended to be undertaken in this House. We wanted the Government to be bound by a voting mandate of this House. After all, in a democracy, vote best reflects what the opinion of the people or their representatives is. And, it's not only on price rise that this is happening.

Look around the whole country. What is going on? The Valley in Kashmir is going out of control and the Government is completely clueless. There is not even a sign of what a possible roadmap or line of action would be. You have a civil war going on within the Government and the ruling alliance as to how to deal with the Maoist violence. You start a dialogue with Pakistan and suddenly you realise at the end of the dialogue that it ended in a misadventure. On the economic front and the price rise situation, we only find these tall assurances for the last 1-1/2 years that prices would soon start to moderate. In fact, the very credibility of the economists who administer the economy of this Government is at stake. They cannot foresee what's really going to happen. And what are the positives as far as this Government is concerned?

Just now, Members were mentioning about the Commonwealth Games and we saw that it's a great global event which is going to take place. We hope for a positive. All we are seeing is generation of private wealth in the name of common wealth. That's all that is happening till date. Let there be no doubt that it's not the stadiums which are leaking, the very coffers of this Government continue to leak by the day as far as this event is concerned. And we find that your other actions are that you start misusing governmental institutions, institutions like the investigative agencies of this Government. We were hoping to be educated through your CBI and your investigative agencies as to what went wrong in the 2G spectrum. But, for the last one year, we haven't got a single statement of truth. We were hoping to be told that some of the

worst things have been happening in the allocation of National Highways. Even the culprits are not being allowed to be interrogated. But, your only positive is that you use the agency against Opposition-ruled Governments and Opposition leaders.

What is the kind of drift in this Government that we expect them to really solve the problem of price rise and inflation? We earlier used to speak in terms of alternative power centres within the UPA. Well that was a criticism which is now becoming an old one. Almost every ally is becoming a power centre. Somebody sits in Kolkata and you can't discipline them. Somebody sits in Chennai and, therefore, that is an island of governance itself. You can't interfere in those Ministries. If this is what is happening to this Government, in debate after debate, do we seriously expect the Government to come and make a resolution as far as price rise is concerned?

The Minister responsible for building highways is at war with the Planning Commission. The rest of the Government is busy giving a drubbing to the Home Minister. The Environment Minister is stalling projects of every other Ministry. And we all become silent spectators. The Prime Minister is a spectator when this is going on. What do we really expect this Government to do?

Sir, containing inflation or reducing the prices for this Government is like a mirage, is like a drive through a desert. They tell you that in just two more months prices will moderate, but then you see at the end of your drive the distance gets further and further down. When the debates go on, what are we told? Well, we had a bad season last year; there was a drought in some parts of the country; the foodgrain production itself went down and, therefore, prices of foodgrain itself got affected. Then we are told the global prices have skyrocketed; the international oil prices have gone out of control. Look at the rest of the world what seems to be happening. It is a Government of alibi. But no alibi is a substitute really for the tears and hunger of the common man, of the poor people. You had buffer stocks, as far as your shortages are concerned. You had a huge amount of buffer stock. In fact, your buffer stock, as per your Economic Survey earlier this year, was far more than your normal requirement. How did you manage it? Was it this kind of callousness as far as the Government is concerned,

that you had a buffer stock, you had a shortage in production, and yet you have foodgrains rotting? One figure the Government mentioned was 61,000 metric tones. It is an understatement of what is rotting outside. Now the foodgrain is rotting. But people are going hungry and because of shortage the foodgrain prices are moving up. It is a kind of a callousness and irresponsibility almost unmatched in history.

For a Government which wants and we are all anxiously awaiting for the Food Security Act, is this the kind of food management today that we expect from this Government? Let us come to the first reason. What is the global trend in inflation today? The global trend in inflation is that prior to 2008 several countries saw before the slowdown a double-digit inflation. At that time we were comfortably placed at about 7 and 7.2 per cent. Today, if you look at the figures of food inflation in similarly placed economies, Brazil is now down to 6 per cent; Sri Lanka - 2 per cent; China - 1 per cent and we went up climbing to almost 23 per cent and now coming down. That is as far as the global figures are concerned. In a situation of this kind, as far as the inflation figures are concerned, if you look at the similar placed economies, the only satisfaction we may get is Pakistan has higher inflation than us. But except that, Bangladesh is lesser. It is 1.61 per cent in the case of Malaysia. Look at the Asian countries: It 3.34 per cent for Thailand, 5.05 per cent for Indonesia, 4.28 per cent for Philippines and 3.10 per cent for China. Aren't these countries affected by the global process? The same factors that apply to them continue to apply to us. Then, we are being told that the world situation is bad and, therefore, the food prices in India are in this kind of a situation. Well, the global oil prices went up. This whole issue of oil prices has been raised repeatedly. In the last one year, oil prices have been between 70 to 79 dollars per barrel. Now, the variation, as far as global prices are concerned, is two to three dollars; they go up and down. But you have had a huge increase. And every time we are told, either we make the oil companies sick, or the Government continues to subsidise them because the Government cannot continue to bleed the oil companies. But the truth of the matter is that a very large part that the Indian consumer is today paying is really taxes to various Governments. You have customs duty. You have excise

duty. You have State level taxes. If you look around, what kinds of prices are similar countries paying? China pays a little over Rs.31 a litre for petroleum, Malaysia, Rs.25 and Pakistan, Rs.44. Their levels of taxation are entirely different. Your oil companies have all made profit. Now, the argument given is that they have made profit because the Government subsidized them. Yes, the Government subsidized them, but if the total taxation, that of the Centre and States, is between 50 and 55 per cent, depending on what the taxes in a given State are, then the volume of what you are collecting from the consumer today is almost as much as what you are subsidizing the oil company itself. If your subsidy to the oil companies is Rs.53,000 crores, then what are you collecting from the consumer by way of taxes in these three categories? Last year, it was between Rs.84,000 and Rs.90,000 crores; this year it is likely to be Rs.1,20,000 crores. So, you collect Rs.1,20,000 crores from the companies, you subsidize them to the extent of Rs. 53,000 crores and you say they are surviving only on account of your subsidy. What would any country have done under these circumstances? Your entire fiscal policy and taxation policy with regard to petroleum products, whether it is diesel or other products, is that you have an *ad valorem* rate of duty. So, every time the prices go up, the quantum of taxation also goes up. If you are collecting 51 per cent from a consumer in a given State, that 51 per cent would also go up, depending on the value of the crude oil going up. Therefore, while the value of crude oil itself is only Rs. 20 to 23 a litre, the rest of it we are paying as taxes. Now, India pays 51 per cent; let us look at what happens with our neighbours; Pakistan pays 30 per cent of the total tax on petrol; Sri Lanka pays 37 per cent.

On diesel, we, in India, pay 30 per cent taxes. There are countries which are paying only 15 per cent. Pakistan charges only 15 per cent. Therefore, you charge higher taxes. The prices in the last one year have not risen to the extent that you thought they would rise; they have remained in that 75 to 80 dollar bracket. Then, if there is any increase in prices, at least, have a revenue-neutral policy as far as your taxes are concerned. Therefore, irrespective of the oscillating prices, our revenue would remain as far as oil is concerned, and the burden on the common man will be offset against that. But we don't do it.

Therefore, you have a situation where prices across the world in most similarly placed economies are not to the extent of what we think that they are. This year, we hope because of a good monsoon we will have a bumper harvest. But, the problem will be where to store this. We are now told, and that is a routine explanation being given, 'Well, we have increased the minimum support price as far as the farmer is concerned. The moment we increase the minimum support price, the effect of that increase in the minimum support price is that the prices to the consumers are naturally bound to go up.'

Sir, this is half true. This is half true for the reason that one of the rationales for increasing the minimum support price is that the farmer gets more. The moment the farmer is incentivised for a particular crop, the farmer then starts producing more of that crop. The rationale behind the increase of the minimum support price is to see to it that the farmer gets more, production increases because that crop is incentivised and, in the long run, that takes care and levels the prices down. So, you refer to the first part of your argument relating that the long-term effect of the minimum support price increase should be, that the production in that crop has to increase and the prices have to level out. Now, what seems to be happening is a new problem. Instead of using your buffer stocks for the consumers so that you can flatten the market a little, your buffer stocks are today lying; the FCI, I am told has a limited capacity; there is a pucca capacity, there are also areas where they cover with plastic and the third category is what is today lying in playgrounds, it is lying in the fields, it is lying in schools, it is lying along the railway tracks and it is rotting.

So, the irony of India's economy is that you have a huge starvation amongst the particular sections and you also have the largest destruction of foodgrains because of bad management of the foodgrains economy. This is what seems to be happening as far as the foodgrains economy is concerned.

I have recently come across reports which have not been contradicted that in some places; and they showed the visuals on television; that in an FCI godown in Jaipur, they found liquor stocks and the foodgrains outside! In Kanpur, I am sure, my friends from U.P. would try, verify and confirm and see that if this is there set

right this wrong. In Kanpur, amongst the State warehousing corporation, the foodgrain is outside and the godowns have been let out to Pepsi and ITC because they give a higher rent! If this is how we are going to manage the foodgrain economy, then certainly we will have a situation where the two principal contributors, the food prices as also the oil prices, are enough to harass the consumers. Both require adequate and proper management so that the consumer himself does not get burdened to the extent that he has been burdened today. Has the farmer been hugely burdened? I recently came across a document, which is available on the net; it was the Department of Consumer Affairs presentation to the Core Group Meeting of the Government. Between the farmer, the farm gate as they call it, and the retailer; I can understand the cost moving up because there is marketing cost, there is some profit which the middle man will have, there is a transportation cost; so, it cannot be identical. But, between even the wholesale mandis and the retailer, what is the management that we are having? This is also a responsibility of the State Governments, I concede there have been products where their own figures for the Core Group are that between the *mandis* and the retailer, the markup, because the vegetable costs are going up recently, in potato was as high as 88 per cent; in onion, it was 126 per cent. And amongst the vegetables, these are the two most valuable vegetables, as far as the common consumer is concerned.

Sir, I think the Government needs to have a little compassion, as far as the consumer is concerned; as far as the ordinary citizen is concerned. After all, what is this unprecedented price-rise of general inflation over 10 per cent, moving up; food inflation going up to 23 per cent and then coming down, and our sense of satisfaction is, now it is only 12 per cent. Sir, 12 per cent is a very high rate of inflation. And, therefore, the net effect of it is, it becomes like an unlegislated tax, as far as the common man is concerned. A part of his pocket and what is there in gets chipped, as far as the common citizen is concerned. The moment it is 15 per cent or 20 per cent or anything more than 10 per cent, his purchasing power to that extent is eroded. If he has to buy *dal*, it is less; if he has to buy *roti*, it is less. In fact, when food prices grow up by 10 to 20 per cent, in Indian culture and society the sense of satisfaction

used to be that I have my first income in the family, at least, the *dal*, *roti* is taken care of. This *dal*, *roti* also gets snatched when inflation and price-rise is of this kind. The entire purchasing capacity of the consumer gets completely eroded, and disturbed by this. For those, the pensioners, the salaried people, the lower-middle class people who may have some savings for bad time, for old age, the interest that they get is today much lower than the value of inflation, the rise of inflation. Their savings are getting eroded. The effect of all this is that it affects every citizen. As far as the larger economy is concerned, the Prime Minister knows better than anyone of us. An inflationary expectation leads to a situation where you don't want to spend more at this time. You want to save for your bad day. Therefore, this affects in the long run your entire growth rates. The other countries in the world do not have that level of inflation which we have. That is why I did not read United States or Western European countries' inflation. When we compare our products with the countries we are competing with, which are similarly placed, our products in an inflationary economy are going to cost more than their products. It is entirely going to affect each and every aspect, as far as our economy is concerned. Then, Sir, the wealthier can always hedge inflation. They know how to get resources. The poor man's ability to even avoid it does not exist. Inequity and inequalities in society therefore go up. They are affected much worse than this. What do we, Sir, do under these circumstances? The Governmental statistics are not giving us much satisfaction. We are still in the Government depending on the old concept of the Wholesale Price Index. And, this ten per cent plus inflation today, 10 to 11 per cent, is the Wholesale Price Index. Most countries in the world have done away with this Wholesale Price Index. It is not a true and honest reflection of the prices at which you get products in the market. The Consumer Price Index of various categories, whether for the industrial workers or for others, is closer to truth, if not the entire truth. But, this WPI figure that we are regularly releasing is no representative of what the exact position of price-rise is. We have urged the Finance Minister earlier; I am again urging him that, at least, this is one change he wants to bring about, at least, the country must know the truth of where we stand. People with meager or inadequate money in their pockets must

know whether they are in a position to spend.

Sir, as I said in the beginning, each and every *alibi* that the Government has been giving, seems inadequate. You have buffer. It is not food shortage that has caused this price rise; it is your management which has caused this price rise. The international oil prices went up to 142 dollar at one stage. In the last 14 months of this UPA-II, they are in this 75 dollar range. They have not risen abnormally. So, don't blame the oil prices. Your taxes on the oil prices are going up and that is what is hurting the consumer. If you say that there is global inflation, the global figures do not seem to suggest that. Therefore, these poor *alibis* are not a substitute, as I said, to the tears and hunger of the common man. Sir, what is at stake today is a lot more. When this Government was voted to power we had expectations that this would be a more stable Government and, therefore, more decisive Government. Your Government also said with a sense of smile, "We do not have to depend on the crutches of the Left now, and, therefore, we can independently take decisions." But what has happened in the last 14 months? The Left has gone out, the country seems to be getting taken over by the 'extreme' Left and the Government is watching helplessly. So far since 11th of June, we have not heard a single positive statement about what is your roadmap or thinking and how do you intend to tackling the situation in the Valley. Day after day a scandal or scam comes out. The arrogance of power may only give you only one weapon in your hand that 'we will teach the Opposition by misusing this Governmental authority or these Governmental authorities.' But these eventually become counterproductive. You can continue to punish us, but do not punish the common man.

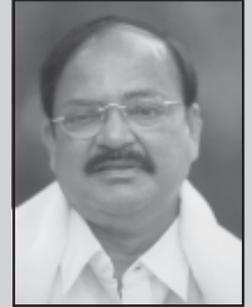
At the end of the day please realize this. The hon. Prime Minister is here, with my utmost respect and affection for him, let me conclude by saying that the credibility of the economist, who administers the economy of this country, is today at stake. We want that credibility to remain and I hope the Government will take some decisive step and come out of the kind of paralysis that has struck this Government in various fields in the last 14 months.

Thank you very much.



UPA intentionally allowing the foodgrains to rot Venkaiah Naidu

Supporting the stand taken by other leaders of BJP on price rise, former BJP National President Shri Venkaiah Naidu MP on August 10, 2010 criticized the Union government for ditching the aam aadmi and intentionally allowing the food grains to rot. Full text of his speech:



Sir, the hon. Minister of Agriculture and Food and Public Distribution, time and again, has been giving this assurance. He and everybody in the Government is aware of it, but what is happening is really shocking. Sir, it is really surprising that in spite of a lot of hue and cry in Parliament on one side and in media and from every quarter on the other — hon. Supreme Court also had to intervene in this matter — the Government has not moved and the figures which the hon. Minister has given, I am sorry to say, are far from reality.

The hon. Minister is trying to hide the reality, because there is a glaring lapse on the part of FCI, various other agencies involved and also on the part of the Government for not creating adequate storage facility. It is a crime against the nation. These are not my words. These are the words of the Supreme Court which said that it is a crime to allow food to rot. It is the comment made by the Supreme Court of India. I think, it has also issued a notice to the Government.

In a Parliamentary democracy, if matters have to go to the highest court of land and the court has to intervene, then, what will happen to the system? I am not finding fault with the court for intervening in the matter. It speaks about our weakness in our system. It speaks about the failure of the Government. The Government should have been alive to the reality of the situation and should have created enough storage facilities.

Even according to the statistics given by the hon. Minister, the storage available in the country is not at all sufficient. It is everybody's knowledge. Sir, we have total foodgrains of 5.18 lakh tones and pucca storage facilities available in the country, both by Central, State and private agencies, stands at 4.20 lakh tones. Sir, 1.78 lakh foodgrains are stored under tarpaulin!

Today, we have reports from various parts of the country that these foodgrains are getting rotted, in certain areas, because of flood and, in certain areas, because of other menace.

Sir, we are a country where 40 crore people are living Below Poverty Line. Sir, on the one hand, they are not able to get adequate foodgrains for their livelihood and, on the other, you are criminally negligent and allowing to rot a huge quantity of foodgrains which the Government has procured at a cost of the public exchequer. You just compare these two. Sir, Commission-after-Commission and Committee-after-Committee highlighting this fact that poverty levels are increasing in the country. That is a different matter. I am not going into that. When the poverty levels are increasing, is it not the duty of the Government to see that procurement, storage and handling is done properly and then they are made available to the people? Here is a Minister who is in-charge of Agriculture, Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Sometimes, I feel that the hon. Minister is overburdened. He himself has said it to the hon. Prime Minister recently. I am happy about it.

Sir, a country of India's size, agriculture needs an independent Minister. The Consumer Affairs, Food and Public Distribution also need an independent Minister. This is not my commentary on the functioning of the hon. Minister. My point is, no human being will

be able to focus enough attention on this issue if he is overburdened.

Food is a major issue. We are going to bring forward the Food Security Act also. That speaks of the seriousness of the matter. I would like the Minister to tell the House specifically what additional storage capacity has been created by the Food Corporation of India itself, not the area that you got through private people; that is a secondary point. How much additional storage capacity, year wise, has been created by the Food Corporation of India in the last five years of this Government? What are your plans, now? The Planning Commission amount, which has been quoted by the hon. Minister, is a peanut. It is very paltry. The problem is going to continue, I am telling you. It is surprising, if this is the approach of even the Planning Commission. They are not able to see the reality. You are procuring food and not able to store it and allowing it to rot and, thus, wasting money. You don't have money and you are borrowing money from outside. Out of the budget of Rs. 10,4,000 crores, nearly Rs. 4,48,000 crores have been borrowed from outside. You don't have budgetary resources. Whatever resources you have, you are not able to spend it properly. You are allowing the foodgrains to rot. As the Supreme Court opined, this is really a crime.

I would like to know from the hon. Minister what his action plan is for creating additional storage space. The *panchayats* should be involved. There has to be godowns in the rural areas. Also, there has to be cold-storage units, refrigerating vans. These are the need of the hour. Time and again, we are bringing to the notice of the Government the need to increase storage facilities. And, then, link it to the private people also. And, then, make them to have affordable credit, with a minimum interest. Then only you will be able to solve this problem. The food production is increasing; I am happy about it. The Government is sometimes also forced by all of us to procure because the markets are not behaving properly and positively. So, that being the case, additional space creation of both, the godowns as well as storage facilities for the perishable goods, and also the refrigerating vans are the need of the hour.

Twenty per cent of the production of the country is going waste

every year. Twenty per cent! Twenty per cent is not an ordinary thing. One of the figures that was made available to us is that the foodgrains worth Rs. 17,000 crores have been lost. Rs. 17,000 crores is not an ordinary amount.

The hon. Prime Minister had, five years back, said in the NDC meeting, “India to become international food supplier”. We are not able to supply food to our own people. The intention of the Prime Minister was, undoubtedly, good. Five years back, he had also set up a Committee under the chairmanship of the Minister of Food. I would like to know from the hon. Minister what has happened to that committee. What were the recommendations and conclusions of that committee? Then, what is the action plan on the observations made by the Prime Minister and the committee, which was constituted under your own chairmanship?

Sir, this has been happening every year. And, some sort of assurance is given, every year, in the House. You had given some assurance in last August also. You had given assurances earlier also. There has to be a time-bound action programme to take care of this. It is not sufficient to say that eight officers have been suspended. What is the crime? What is the punishment? The quantum of crime for the wastage of foodgrains is very serious. Now, you are saying that eight officers have been suspended here and there. The problem is that of bad maintenance and pilferage. And, there are some reports that suggest that you are not giving proper rent. Therefore, some of the godowns have been given on rent for storing whisky, cold drinks and other things. I can't find fault with them because they are commercial entities. But it is the duty of the Government to create additional storage facilities. The Government has utterly and miserably failed in its responsibility. It has become totally insensitive to the sufferings of the people.

The Government definitely needs to explain what the action plan is that they have so far implemented. What is the action plan that you have in your mind, backed with the support of Planning Commission and also the Finance Ministry to supplement the storage facilities in the country? Otherwise, Sir, nobody will forgive this

Government. I am sorry to say that somehow enough attention has not been paid to this issue. The problem is simply that of inadequate and improper storing space in the country. The Government has to address this issue on a war footing. You cannot allow the hungry people to die. We are also getting reports about starvation deaths, malnutrition deaths in many States, including the State of Maharashtra, to which the hon. Minister belongs to.

In Haryana, in Sirsa, three lakh tonnes of foodgrains were lost because of heavy floods. In Gondia, Maharashtra, 56,000 sacks of grains were lost because it was kept in the open. So, this is official apathy, callous attitude of the Government, non-availability of space and, then, the Food Corporation is becoming a white elephant and not doing adequately to handle the situation. All this is resulting in the present situation. So, I would like to know from the hon. Minister what is the road map, what is the action plan, backed with allocation? That is the main issue.

